पंजाब केसरी
SAT,21 FEBRUARY 2026
EDITION: HIMACHAL , PAGE NO. 5

पैंशनर्स कॉर्पस फंड को राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जाएगा : डा. राजेश

धर्मशाला : स्कूल शिक्षा बोर्ड में पैंशन फंड ट्रस्ट की बैठक में उपस्थित बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा व अन्य। (ब्यूरो)

धर्मशाला, 20 फरवरी (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पैंशनर्स के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ी और निर्णायक पहल की है। बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने 6 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पैंशन फंड ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर पैंशनर्स के भविष्य को लेकर कई बड़े बदलावों का ऐलान किया है।

इस बैठक में कुछ दिन पहले हुए विचार-विमर्श के 48 घंटों के भीतर ही महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि पैंशनर्स की वर्षों की सेवा का सम्मान करते हुए उनके अधिकारों और आर्थिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत अब पैंशन फंड ट्रस्ट की बैठकों में निरंतरता लाई जाएगी और प्रत्येक वर्ष इनका नियमित आयोजन होगा, ताकि कार्यप्रणाली की समय-समय पर समीक्षा हो सके।

पैंशनर्स की जीवन भर की जमा पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए बोर्ड ने निर्णय लिया है कि पैंशनर्स कॉर्पस फंड को अब किसी भी प्रतिष्ठित राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जाएगा, जहां अधिकतम लाभ के साथ-साथ पूर्ण पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। डा. राजेश ने दो टूक कहा कि यह पहल केवल एक औपचारिकता या आश्वासन नहीं है, बल्कि प्रशासनिक दृढ़ता का प्रमाण है, जिसके ठोस परिणाम अब धरातल पर दिखाई देंगे।

अब ट्रस्ट की बैठक में बैठेंगे 2 पैंशनर्स प्रतिनिधि

अब ट्रस्ट समिति में 2 पैंशनर्स को नामित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा, जिससे उनकी वास्तविक समस्याओं को सीधे बोर्ड के समक्ष रखा जा सकेगा और समाधान अधिक प्रभावी व व्यावहारिक बनेंगे। डा. राजेश शर्मा ने भरोसा दिलाया है कि बोर्ड का लक्ष्य पैंशनर्स के धन की सुरक्षा, समय पर भुगतान और संचालन में पूर्ण पारदर्शिता लाना है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी, तो इन विषयों को शासन स्तर पर भी मजबूती से उठाया जाएगा ताकि पैंशनर्स का सम्मान और उनकी आर्थिक सुरक्षा पूरी मजबूती के साथ सुनिश्चित की जा सके।

Anant Gyan 21-02-2026

शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष का सुपरफास्ट फैसला, अब ट्रस्ट की बैठक में शामिल होंगे दो पेंशनर्स प्रतिनिधि

अनंत ज्ञान

ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पेंशनर्स के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ी और निर्णायक पहल की है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने छह वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पेंशन फंड ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर पेंशनर्स के भविष्य को लेकर कई बड़े बदलावों का ऐलान किया है।

इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि डॉ. शर्मा ने केवल चर्चा ही नहीं की, बल्कि हालिया विचार-विमर्श के मात्र 48 घंटों के भीतर ही महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि पेंशनर्स की वर्षों की सेवा का सम्मान करते हुए उनके अधिकारों और आर्थिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत अब पेंशन फंड ट्रस्ट की बैठकों में निरंतरता लाई जाएगी और प्रत्येक वर्ष इनका नियमित आयोजन होगा ताकि कार्यप्रणाली की समय-समय पर समीक्षा हो सके। पेंशनर्स की जीवन भर की जमा पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए बोर्ड ने निर्णय लिया है कि पेंशनर कॉर्पस फंड को अब किसी भी प्रतिष्ठित राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जाएगा, जहां अधिकतम लाभ के साथ-साथ पूर्ण पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। डॉ. शर्मा ने दो टूक कहा कि यह पहल केवल एक औपचारिकता या आश्वासन नहीं है, बल्कि प्रशासनिक दृढ़ता का प्रमाण है, जिसके ठोस परिणाम अब धरातल पर दिखाई देंगे।

पेंशन फंड ट्रस्ट की बैठक में डॉ. राजेश शर्मा व अन्य। अनंत ज्ञान

पेंशनर्स को निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए बोर्ड ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब ट्रस्ट समिति में दो पेंशनर्स को नामित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा, जिससे उनकी वास्तविक समस्याओं को सीधे बोर्ड के समक्ष रखा जा सकेगा और समाधान अधिक प्रभावी व व्यावहारिक बनेंगे। डॉ. राजेश शर्मा ने भरोसा दिलाया है कि बोर्ड का लक्ष्य पेंशनर्स के धन की सुरक्षा, समय पर भुगतान और संचालन में पूर्ण पारदर्शिता लाना है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी, तो इन विषयों को शासन स्तर पर भी मजबूती से उठाया जाएगा ताकि पेंशनर्स का सम्मान और उनकी आर्थिक सुरक्षा पूरी मजबूती के साथ सुनिश्चित की जा सके।

◆ 48 घंटे में समाधान, अब पेंशनर्स खुद तय करेंगे अपना भाग्य

Dev Bhoomi Mirror
21-02-2026

शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष का 'सुपरफास्ट' फैसला

निशा/देवभूमि मिरर

धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पेंशनर्स के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ी और निर्णायक पहल की है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने छह वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पेंशन फंड ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर पेंशनर्स के भविष्य को लेकर कई बड़े बदलावों का ऐलान किया है। इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि डॉ. शर्मा ने केवल चर्चा ही नहीं की, बल्कि हालिया विचार-विमर्श के मात्र 48 घंटों के भीतर ही महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि पेंशनर्स की वर्षों की सेवा का सम्मान करते हुए उनके अधिकारों और आर्थिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

इस नई व्यवस्था के तहत अब पेंशन फंड ट्रस्ट की बैठकों में निरंतरता लाई जाएगी और प्रत्येक वर्ष इनका नियमित आयोजन होगा ताकि कार्यप्रणाली की समय-समय पर समीक्षा हो सके। पेंशनर्स की जीवन भर की जमा पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए बोर्ड ने निर्णय लिया है कि पेंशनर कॉर्पस फंड को अब किसी भी प्रतिष्ठित राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जाएगा, जहाँ अधिकतम लाभ के साथ-साथ पूर्ण पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। डॉ. शर्मा ने दो टूक कहा कि यह पहल केवल एक औपचारिकता या आश्वासन नहीं है, बल्कि प्रशासनिक दृढ़ता का प्रमाण है, जिसके ठोस परिणाम अब धरातल पर दिखाई देंगे।

पेंशनर्स को निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए बोर्ड ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब ट्रस्ट समिति में दो पेंशनर्स को नामित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा, जिससे उनकी वास्तविक समस्याओं को सीधे बोर्ड के समक्ष रखा जा सकेगा और समाधान अधिक प्रभावी व व्यावहारिक बनेंगे। डॉ. राजेश शर्मा ने भरोसा दिलाया है कि बोर्ड का लक्ष्य पेंशनर्स के धन की सुरक्षा, समय पर भुगतान और संचालन में पूर्ण पारदर्शिता लाना है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी, तो इन विषयों को शासन स्तर पर भी मजबूती से उठाया जाएगा ताकि पेंशनर्स का सम्मान और उनकी आर्थिक सुरक्षा पूरी मजबूती के साथ सुनिश्चित की जा सके।

शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने 48 घंटे में निपटाई पेंशनरों की समस्याएं

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-धर्मशाला

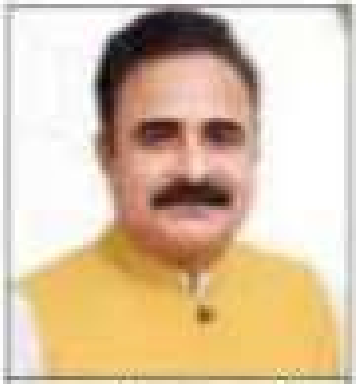

राजेश शर्मा

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पेंशनर्ज के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ी और निर्णायक पहल की है। बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने छह वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पेंशन फंड ट्रस्ट की महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित कर पेंशनर्ज के भविष्य को लेकर कई बड़े बदलावों का ऐलान किया है। डा. शर्मा ने केवल चर्चा ही नहीं की, बल्कि हालिया विचार-विमर्श के मात्र 48 घंटों के भीतर ही महत्त्वपूर्ण निर्णय लेकर उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि पेंशनर्ज की वर्षों की सेवा का सम्मान करते हुए उनके अधिकारों और आर्थिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

ट्रस्ट की बैठक में बैठेंगे दो पेंशनर प्रतिनिधि

पेंशनर्ज को निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए बोर्ड ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब ट्रस्ट समिति में दो पेंशनर्स को नामित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। जिससे उनकी वास्तविक समस्याओं को सीधे बोर्ड के समक्ष रखा जा सकेगा और समाधान अधिक प्रभावी व व्यावहारिक बनेंगे।

दिव्य हिमाचल
Sat, 21 February 2026
https://epaper.divyahima

दैनिक सवेरा टाइम्स
अंधेरे से उजाले की ओर...

शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष का 'सुपरफास्ट' फैसला

- 6 साल का सूखा खत्म, डॉ. राजेश शर्मा ने बदली व्यवस्था
- अब ट्रस्ट की बैठक में बैठेंगे दो पेंशनर प्रतिनिधि

48 घंटे में समाधान, अब पेंशनर्स खुद तय करेंगे अपना भाग्य

सवेरा न्यूज/यशपाल सिंह

धर्मशाला, 20 फरवरी : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पेंशनर्स के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ी और निर्णायक पहल की है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने छह वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पेंशन फंड ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर पेंशनर्स के भविष्य को लेकर कई बड़े बदलावों का ऐलान किया है। इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि डॉ. शर्मा ने केवल चर्चा ही नहीं की, बल्कि हालिया विचार-विमर्श के मात्र 48 घंटों के भीतर ही महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है।

बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि पेंशनर्स की वर्षों की सेवा का सम्मान करते हुए उनके अधिकारों और आर्थिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत अब पेंशन फंड ट्रस्ट की बैठकों में निरंतरता लाई जाएगी और प्रत्येक वर्ष इनका नियमित आयोजन होगा ताकि कार्यप्रणाली की समय-समय पर समीक्षा हो सके। पेंशनर्स की जीवन भर की जमा पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए बोर्ड ने निर्णय लिया है कि पेंशनर कॉर्पस फंड को अब किसी भी प्रतिष्ठित राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जाएगा, जहां अधिकतम लाभ के साथ-साथ पूर्ण पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। डॉ. शर्मा ने दो टूक कहा कि यह पहल केवल एक औपचारिकता या आश्वासन नहीं है, बल्कि प्रशासनिक दृढ़ता का प्रमाण है, जिसके ठोस परिणाम अब धरातल पर दिखाई देंगे। पेंशनर्स को निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए बोर्ड ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। डॉ. राजेश शर्मा ने भरोसा दिलाया है कि बोर्ड का लक्ष्य पेंशनर्स के धन की सुरक्षा, समय पर भुगतान और संचालन में पूर्ण पारदर्शिता लाना है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी, तो इन विषयों को शासन स्तर पर भी मजबूती से उठाया जाएगा ताकि पेंशनर्स का सम्मान और उनकी आर्थिक सुरक्षा पूरी मजबूती के साथ सुनिश्चित की जा सके।

6-Year Drought Ends, Dr. Rajesh Sharma Changes System

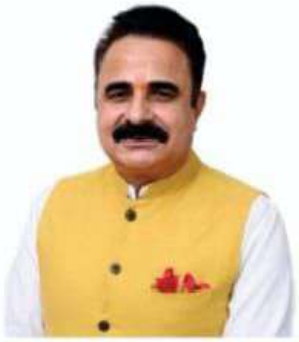

SANJAY AGGARWAL

DHARAMSHALA FEB 20 : The Himachal Pradesh School Education Board has taken a major and decisive initiative to protect the interests of pensioners. Board Chairman Dr. Rajesh Sharma, after a six-year hiatus, convened a crucial meeting of the Pension Fund Trust, announcing several major changes regarding the future of pensioners. The most significant aspect of this meeting was that Dr. Sharma not only discussed the matter but also made significant decisions within just 48 hours of the recent deliberations, preparing to implement them in a phased manner. The Board Chairman clarified that, while respecting the years of service of pensioners, their rights and financial security will be given top priority.Under this new system, the Pension Fund Trust meetings will now be consistent and held regularly every year to ensure periodic review of the functioning. To safeguard pensioners' lifelong savings, the Board has decided to deposit the Pensioner Corpus Fund in a reputable nationalized bank, ensuring maximum returns and complete transparency and security. Dr. Sharma stated unequivocally that this initiative is not merely a formality or a promise, but a testament to administrative resolve, the concrete results of which will now be visible on the ground. The Board has taken another revolutionary step to empower pensioners in decision-making. Two pensioners will now be included as nominated members on the Trust Committee, enabling their genuine concerns to be directly addressed to the Board, making solutions more effective and practical. Dr. Rajesh Sharma assured that the Board's goal is to ensure the safety of pensioners' funds, timely payments, and complete transparency in operations.

21 FEBRUARY, 2026 DHARAMSHALA

The Sunny Times

'SUPERFAST' DECISION BY BOARD CHAIRMAN PENSIONERS TO HELP SHAPE THEIR OWN FUTURE

Transparent, Timely, Transformative: HPBOSE Overhauls Pension Fund System

Dr. Rajesh Sharma Ends 6-Year Pension Freeze

Sunny Mahajan

In a decisive administrative move, the Himachal Pradesh Board of School Education (HPBOSE) has announced sweeping reforms aimed at safeguarding the interests of its pensioners. Board Chairman **Dr. Rajesh Sharma** convened a long-pending Pension Fund Trust meeting after a gap of six years and unveiled a series of structural changes designed to ensure financial security, transparency, and participatory governance.

What stands out is the speed of implementation. Within just 48 hours of detailed deliberations, the Chairman moved beyond assurances and initiated concrete steps to operationalize key decisions in a phased manner.

"The objective is to make the decision-making process more practical, inclusive, and solution-oriented. If required, pension-related matters will also be raised at the government level to secure broader institutional support." - Dr. Rajesh Sharma

Corpus Fund to Be Secured in Nationalized Banks

In a significant financial safeguard, the Board has decided that the Pensioners' Corpus Fund will now be deposited in reputed nationalized banks. This move is intended to maximize returns while ensuring complete transparency and security of funds. The Chairman clarified that the reform is not merely symbolic but reflects firm administrative commitment. The Board's focus remains on ensuring the safety of pensioners' lifetime savings and maintaining financial discipline in fund operations.

Focus on Transparency and Timely Payments

The Board reiterated its commitment to ensuring timely disbursement of pensions and maintaining full transparency in fund management. With structural reforms now underway, pensioners are expected to benefit from improved financial stability and more accountable governance.

The swift turnaround in decision-making has been viewed as a proactive administrative step, signaling a renewed commitment toward institutional responsibility and pensioners' welfare.

Amar Ujala 21-02-2026

एलडीआर टेस्ट की फीस जमा न करवाने वाले दे सकेंगे पेपर

शिक्षा बोर्ड परीक्षा में बैठने देगा, पर जारी नहीं करेगा परिणाम

विपिन चौधरी

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 22 फरवरी को आयोजित होने वाली सीमित सीधी भर्ती (एलडीआर) के लिए बोर्ड की ओर से निर्धारित किए गए शुल्क को जमा न करवाने वाले अभ्यर्थी भी टेस्ट में बैठ सकेंगे। इन अभ्यर्थियों के परिणाम को शिक्षा बोर्ड तब तक जारी नहीं करेगा, जब तक वे फीस जमा नहीं करवा देते।

जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 23 दिसंबर से 15 जनवरी तक ऑनलाइन माध्यम से सीमित सीधी भर्ती (एलडीआर) के लिए आवेदन मांगे थे। 1,427 पदों को भरने के लिए होने वाली इस लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से 3,000 रुपये शुल्क जमा करवाने को कहा था।

ये पद केवल हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में सेवारत एसएमसी शिक्षकों के लिए आरक्षित थे। इस दौरान जिन्होंने न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो और जो एसएमसी नीति 17-07-2012 के तहत नियुक्त थे और जिनके पास प्रासंगिक एवं लागू आर एंड पी नियमों के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है, वही इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र थे। इसके बाद स्कूल शिक्षा बोर्ड के पास 1534 आवेदन पहुंचे थे, लेकिन इनमें से 97 अभ्यर्थियों ने फीस ही जमा नहीं करवाई थी। इसके चलते शिक्षा बोर्ड ने इन आवेदनों को रद्द करने की बात कही थी। वहीं अब शिक्षा बोर्ड ने फीस जमा न करवाए जाने वाले इन अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उन्हें 22 फरवरी को धर्मशाला, मंडी और शिमला में होने वाले टेस्ट में बैठ सकेंगे।

बोर्ड सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि फीस जमा न करवाने वाले परीक्षा दे सकेंगे, लेकिन उनके परिणाम को फीस देने के बाद ही घोषित होंगे।

यूआईटी के बीटेक के 24 छात्रों को मिला नौकरी का ऑफर

शिमला। हिमाचल विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 24 बीटेक विद्यार्थियों का देश की नामी कंपनियों में आकर्षक सैलरी पैकेज के साथ प्लेसमेंट हुआ है। नामी कंपनी इंफोसिस की ओर से जेपी विश्वविद्यालय वाकनाघाट में जून 2025 और जनवरी 2026 में दो बार हुए कैंपस इंटरव्यू में शामिल हुए विद्यार्थियों में संस्थान के बीटेक आइटी, सीएसई और इसीई के 22 विद्यार्थियों का 36 लाख के वार्षिक सैलरी पैकेज के लिए चयन हुआ है। वहीं, दूसरे दौर की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए दो विद्यार्थियों का क्रमशः 10 लाख वार्षिक के साथ एक लाख नियुक्ति बोनस और 6.5 ला वार्षिक के साथ 75,000 नियुक्ति बोनस के पैकेज के लिए चयनित हुए है। विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान (यूआईटी) के निदेशक प्रो. अमरजीत सिंह ने संस्थान के विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए संस्थान के आईटी और सीएसई के प्लेसमेंट अधिकारी सुनील कुमार और डा. राजेश चौहान और प्लेसमेंट पाने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। संवाद